CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH LUCKNOW

Original Application No. 273/2006

This the 22nd day of October, 2012

HON'BLE MR. JUSTICE ALOK KUMAR SINGH, MEMBER (J)

HON'BLE MR. S.P. SINGH, MEMBER(A)

Ram Tej Singh aged about 53 years son of Sri Chandra Deo Singh Deputy Postmaster H.S.G-I, Gonda.

Applicant

By Advocate Sri R. S. Gupta.

Versus

1. Union of India through the Secretary Department of Post Dak Bhawan, New Delhi.
2. Chief Postmaster General, U.P. Lucknow.
3. Director Postal Services o/o Postmaster General Gorakhpur.
4. Superintendent of Post Offices, Gonda.
5. Senior Superintendent of Post Offices, Lucknow.

Respondents

By Advocate Sri S. P. Singh.

(Reserved on 16.10.2012)

ORDER

By Hon'ble Mr. S. P. Singh, Member (A)

This O.A. has been instituted seeking quashing of orders dated 8.6.2005, 18.3.2002 and 2.11.2001 as contained in Annexure-A-1, A-2 and A-3 with all consequential benefits arrear of pay, promotion etc. with retrospective effect. Annexure -3 is penalty order dated 2.11.2001 passed by the Disciplinary Authority, Annexure-2 is an order dated 18.3.2002 passed by the Appellate Authority and Annexure-3 is an order dated 8.6.2005 passed by the Reversionary Authority.

2. While working as Postal Assistant , Bargaon Post Office from 18.6.1996 to 30.4.1997, Sri Ram Tej Singh, the applicant was served with a charge sheet under Section 16 of CCS(CCA) Rules, 1965 vide Memo No.L/Ahi/UCP/UCR/D-P/61-02 dated 5.9.2001. A true copy of the charge sheet is annexed as Annexure A-7. The applicant was asked to submit his representation, if any, within 10 days on the issue of the charge sheet. The statement of imputation is reproduced as under:

> "श्री रामतेज सिंह उप पोस्ट मास्टर बालपुर के विरूद्व लगाये गये अवचार एवं कदाचार के आरोपों का विवरण।
>
> श्री रामतेज सिंह दिनांक 18/6/96 से 30/4/97 तक डाक सहायक बडगांव के पद पर कार्यरत थे। उपरोक्त श्री राम तेज सिंह दिनांक 17/8/98 की एक प्रार्थना पत्र भेजा कि दिनांक 20/7/96 को वह भूलवश 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) सरकारी नगदी के सांथ अवगीकृत प्राप्ति मद में जमा कर दिया था जो उसे वापस दी जाय। जांचोपरान्त उसका दावा औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण मामला बन्द कर दिया गया तद्नुसार उसे सूचित कर दिया गया था इसके बावजूद भी उपरोक्त श्री रामतेज सिंह पत्राचार के उचित माध्यम की अनदेखी करते हुए सीधे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल लखनउ को दिनांक 9/1/2001 को लिखा। उपरोक्त श्री रामतेज सिंह से इस कार्यालय के पत्र सं0 एल0/अनि/यू0सी0पी0/यू0सी0आर0/गोंडा दिनांक 23/5/2001 द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से सीधे पत्राचार करने के कारण स्पस्टीकरण मांगा गया था परन्तु वह आज तक नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार उपरोक्त श्री रामतेंज सिंह ने डाक तार नियम पुस्तक खण्ड 2 के नियम 614 का उलंघन किया।
>
> अतः आरोपित है कि उपरोक्त कृत्य करके उपरोक्त श्री रामतेज सिंह ने विभाग के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखने में असफल रहते हुए तथा एक सरकारी कर्मचारी के न करने योग्य कार्य करके केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3(i) (ii) (iii) का उलंघन किया।"

3. The applicant for the purpose of preparing and submitting his representation demanded the copies of the letter alleged to have been written by the applicant directly to CPMG, UP, Luckno. Accordingly, the applicant wrote two representations dated 15.10.2001 and 29.10.2001 (Annexure 8 and Annexure-9). According to him, these letters were not made available to him for inspection purpose, nor its copy was supplied for preparing and submitting defence statement/representation. However, on reading of Annexures annexed at Annexure A-8 and A-9,

the applicant fairly concedes that he had submitted two letters simultaneously to the Chief Post Master General on directions of CPMG during his meeting with the Chief Post Master General UP, Lucknow. It is further stated by the applicant in Annexure-8 that the applicant was shown only one letter. He was not shown second letter and demanded it from Sruperindent Post Offices (Annexure 8). The Disciplinary Authority considered defence statement of the applicant dated 29.10.2001(Annexure 9) and passed penalty order dated 2.11.2001 (Annexure A-3). The applicant preferred an appeal dated 19.12.2001 against the order passed by the Disciplinary Authority . The appellate authority did not find any scope of interfering with the order of DA and rejected the appeal of the applicant on 18.3.2002. (Annexure-A-2). The applicant submitted a petition dated 27.2.2002 to Chief Post Master General against the penalty of withholding of one increment for one year without cumulative effect imposed by Superintendent Post Office Gonda Division vide Memo No. L/RR/UCPUCR/DP dated 2.11.2001 and order dated 18.3.2002 by the Director Postal Services Gorakhpur Region. The applicant is aggrieved against the orders annexed by him as at Annexure -1, Annexure -2 , and Annexure- 3 and has approached this Tribunal on the ground that all the points raised in his appeal /petition were not considered by the Appellate Authority as well as Reversionary Authority.

4. The respondents have filed CA on 7.11.2006. According to the respondents, the superintendent post offices, is fully empowered to proceed against the official under Rule 16 of CCS (CCA) Rules 1965. The photo copy of relevant extract of CCS (CCA) Rules 1965 is annexed as Annexure 1 to the CA.

5. According to respondents, the applicant did not submit representation through proper channel to competent authorities and avoiding the channel of correspondence, he wrote direct to CPMG, UP Lucknow on 9.1.2001 and for this irregularity, he was asked to explain

reasons vide letter No. L-1/UCP/UCR/Gonda dated 23.5.2001, but he did not submit his explanation. So the applicant was proceeded against vide office Memo No. L-Inn/UPC/UCR/DF/02 dated 05.09.2001 under Rule 16 of CCS (CCA) Rules 1965 and was awarded punishment of withholding one increment without cumulative effect for one year. The respondents further stated that the petitioner preferred an appeal to the Director Postal Services Gorakhpur, Region Gorakhpur which was rejected by the competent authority vide his Memo No. RRG/Rig/M -19/3/2002 dated 8.3.2002. Aggrieved, from this order, the petitioner subsequently preferred a petition to CPMG UP circle, Lucknow which was also rejected vide memo No. CO, No. Vig/P-29/2003/5 Lucknow dated 8.6.2005. It is further pleaded by the respondents that the Appellate Authority and Reversionary Authority considered all the aspects of the case and decisions were taken on merit in accordance with the rules and regulations applicable to such emloyees in the department. The orders passed by the Appellate Authority and Revisionary Authority are legal, just and proper and are sustainable in the eye of the law. The O.A. is therefore devoid of any merit. It is no legal force and therefore OA should be dismissed with costs.

6. The applicant has filed rejoinder affidavit dated 8.2.2007 reiterating the contents of the O.A.

7. According to the respondents, penalty order dated 2.11.2001, passed by the Disciplinary Authority (Annexure A-3) regarding the applicant that this order has been passed after considering his defence statement dated 29.10.2001. The relevant order is reproduced below:

> "अतः इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 05.09.2001 द्वारा श्री रामतेज सिंह उ0पो0मा0 बालपुर, गोण्डा के विरुद्व निम्नलिखित आरोपों के आधार पर केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम–16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी।
>
> श्री रामतेज सिंह दिनांक 18.06.1996 से 30.04.97 तक डाक सहायक बड़गांव के पद पर कार्यरत थे। उपरोक्त श्री रामतेज सिंह दिनांक 17.08.98 को एक प्रार्थना पत्र भेजा कि दिनांक 20.07.96 को वह भूलवश 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) सरकारी नगदी के साथ अवर्गीकृत प्राप्तियॉ दावा औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण मामला बन्द कर दिया गया तदानुसार उसे सूचित कर

दिया गया था। इसके बावजूद भी उपरोक्त श्री रामतेज सिंह पत्राचार के उचित माध्यम की अनदेखी करते हुए सीधे चीफ पोस्टमास्टर जनरल लखनऊ को दिनांक 09.01.2001 को लिखा। उपरोक्त श्री रामतेज सिंह से इस कार्यालय के पत्र संख्या यल/अनि/यू0सी0पी0/यू0सी0आर0/ गोण्डा दि0 23.05.01 द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से सीधे पत्राचार करने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया था परन्तु वह आज तक नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार उपरोक्त श्री रामतेज सिंह ने डाक तार नियम पुस्तक खण्ड दो के नियम 614 का उल्लंघ्ज्ञन किया।

अतः आरोपित है कि उपरोक्त कृत्य करके उपरोक्त श्री रामतेज सिंह ने विभाग के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखने में असफल रहते हुए एक सरकारी कर्मचारी के न करने योग्य कार्य करके केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3(।)(।।)(।।।) का उल्लघंन किया।

उक्त श्री रामतेज सिंह को यह अवसर दिया गया था कि यदि वे चाहें तो उक्त ज्ञापन की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर अपना बचाव प्रतिवेदन (यदि कोई हो) इस कार्यालय को प्रेषित करें। कर्मचारी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.09.2001 द्वारा चीफ पोस्टमास्टर जनरल महोदय के साथ किये गये पत्राचार का अवलोकन करने की प्रार्थना किया जिसे कि कर्मचारी ने दि0 5.10.2001 को देखा और पुनः दि0 15.10.01 को प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे जो अभिलेख दिखाया गया है उसमें मेरे द्वारा चीफ पो0मा0 जनरल महोदय उ0प्र0 लखनऊ को उनके समक्ष उपस्थित होकर दिये गये दो प्रार्थना पत्रों में से मात्र एक ही देखने को मिला है जबकि मेरा दूसरा मेरे सरकारी आवास विषयक प्रार्थना पत्र मुझे देखने को नहीं मिला है जबकि ये दोनों प्रार्थना पत्र उन्हे साथ–2 उन्हीं के कहने पर दिये गये थे। उसे भी अवलोकन कराया जाय। जिसके जवाब में श्री रामतेज सिंह को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि0 22.10.2001 द्वारा लिखा गया कि दूसरे पत्र से इस आरोप पत्र से कोई संबद्व नहीं है। अतएव आप अपना बचाव प्रतिवेदन इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर भेजे। कर्मचारी ने अपना बचाव प्रतिवेदन दिनांकित 29.10.2001 भेजा जो कि इस कार्यालय में दिनांक 1.11.2001 को प्राप्त हुआ।

मैने कर्मचारी के बचाव अभिकथन तथा अनुशासनिक पत्रावली एवं अन्य संबंधित अभिलेखें का सम्यक अध्ययन किया। कर्मचारी ने अपने बचाव अभिकथन दि0 29.10.01 में कहा कि वह दि0 9.1.01 को डाकपाल गोण्डा के आदेशानुसार डाक वस्तु भण्डार लखनऊ सामान लेने गया था और अपने सरकारी आवास संबंधित कठिनाइयों के बारे में चीफ पोस्टमास्टर जनरल महोदय के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया और उन्ही के आदेशानुसार लिखकर दे दिया। कर्मचारी द्वारा जो प्रार्थना पत्र 9.1.01 को चीफ पी0एम0जी0 लखनऊ को दिया गया है और इस कार्यालय की पत्रावली में है, में भवन संबंधी किसी भी कठिनाई का उल्लेख नहीं किया गया है इस प्रकार उक्त कर्मचारी का उपरोक्त कथन असत्य पाया गया। उसने उस प्रार्थना पत्र में मात्र 1000/– रुपये की वापसी के बारे में ही लिखा है जिसके लिए उसे स्पष्ट उत्तर इस कार्यालय के पत्र दि0 11.05.99 द्वारा सूचना भेज दी गई है और उसे यदि कोई प्रतिवेदन पी0एम0जी0/चीफ पी0एम0जी0 को भेजना था तो उचित माध्यम द्वारा ही भेजना था लेकिन उसने ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा। उसका यह कहना कि इस मामले को उसने पी0एम0जी0 गोरखपुर के गोण्डा प्र0डा0 में उपस्थित रहने पर उनके संज्ञान में लाया गया था लेकिन इस बारे में उसने उन्हे कोई लिखित प्रार्थना पत्र नहीं दिया इसलिए उसे उस स्तर से किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसने अपने बचाव प्रतिवेदन में ऊपर लिखा जा चुका है। यदि कर्मचारी ने उक्त विषयक कोई प्रार्थना पत्र चीफ पी0एम0जी0 कार्यालय लखनऊ में दिया था तो उसका प्रमाण उसे ही प्रस्तुत करना चाहिए। उसने इस प्रपत्र को मांगकर मामले को अनावश्यक रुप से लंबित रखने का प्रयास किया है। जिसे किसी प्रकार से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी के ऊपर लगाया गया आरोप पूर्णतः सिद्व है और जिसके लिए वह कठोर दण्ड का पात्र है। कर्मचारी द्वारा इस प्रकार का

कार्य प्रथम बार किया गया है अतः ऐसा दण्ड दिया ही जाना चाहिए जो अन्य कर्मचारीगण पर भी असर दिखा सके।

अतः मै दिलशेर यादव डाक अधीक्षक गोण्डा एतद्द्वारा उक्त श्री रामतेज सिंह की अगली वेतन बढ़ोत्तरी एक वर्ष तक बिना संचयी प्रभाव के रोके जाने का दण्ड देता हूँ।"

8. The respondents further state that the applicant preferred an appeal dated 19.12.2001, against the order passed by Disciplinary Authority dated 2.11.2001, the Appellate Authority considered all the points raised by the appellant/ applicant. The relevant extract of the order dated 8.6.2005 is reproduced below:-

"2. अपीलार्थी को अधीक्षक डाकघर गोंडा के ज्ञापनांक सं0 दिनांक 5/9/2001 द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा/वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील/नियमावली 1965 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र भेजा गया था। उसके विरूद्व आरोपित था कि

"श्री रामतेज सिंह दिनांक 18/6/1996 से 30/4/97 तक डाक सहायक बडगांव के पद पर कार्यरत थे। उपरोक्त श्री रामतेज सिंह दिनांक 17/8/98 को एक प्रार्थना –पत्र भेजा कि दिनंक 20/7/96 को वह भूलवश रू0 1000/–(रू0 एक हजार मात्र) कसरकारी नगदी के साथ अवर्ग्रोकृत प्रापतियां मद में जमा कर दिया था जो उसे वापस दी जाये। जांचोपरान्त उसका दावा अवचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण मामला बन्द कर दिया गया तद्नुसार उसे सूचित कर दिया गया था इसके बावजूद भी उपरोक्त श्री रामतेज सिंह पत्राचार के उचित माध्यम की अनदेखी करते हुए सीधे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, लखनउ को दिनांक 9/1/2001 को लिखा। उपरोक्त श्री रामतेज सिंह इस कार्यालय के पत्र सं0 एल/अनि/यू0सी0पी0/यू0सी0आर0 गोंडा दिनांक 23/5/2001 द्वारा वरिष्ठ अधिकारी से सीधे पत्राचार करने के कारण स्प टीकरण मांगा गया था परन्तु वह आज तक नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार उपरांक्त श्री राम तेज सिंह ने डाक द्वारा नियम पुस्तक खण्ड दो के नियम 614 का उलंघन किया।

अतः आरोपित है कि उपरोक्त कृत्य करके उपरोक्त श्री रामतेज सिंह ने विभाग के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखने में असफल रहते हुए एक सरकारी कर्मचारी के न करने योग्य कार्य करके केन्द्रीय सिविल सेवा (आचारण) नियमावली 1964 के नियम 3(i) (ii) (iii) का उलंघन किया

3. आरोप–पत्र भेजते समय ज्ञापन में भी निर्देश दिया गया कि वह अपनी इच्छानुसार ज्ञापन प्राप्ति के दस दिन के अन्दर अभ्यावेदन भेज सकते है, यदि वह ऐसा करने में असफल रहते हैं तो यह माना जायेगा कि उन्हें कोई अभ्यावेदन नहीं देना है। अपीलकर्ता दिनांक 29/10/2001 भेजा। अनुशासनिक प्राधिकारी अ0 डा0घ0 गोंडा ने उक्त अनुशासनिक मामले का निस्तारण करते हुए ज्ञापनांक एल/अनि/ यूसीपी/यसीआर/ डीपी/01–02दिनांक 2/11/2001 द्वारा दंडादेश पारित किया जिसके द्वारा अपीलकर्ता की अगली वेतन बढोत्तरी एक वर्ष तक बिना संचयी प्रभाव के रोके जाने का दंड दिया। उक्त दंण्डादेश के विरूद्व उसने अपील दिनांक 19/12/2001 प्रेषित किया जो

इस कार्यालय में दिनांक 21/12/2001 को प्राप्त हुआ। दंण्डादेश दिनांक 06/11/2001 को प्राप्त कराया गया था अपील समय सीमा में है।

4. अपीलकर्ता ने अपनी अपील में निम्नांकित बिन्दुओं को मुख्य रूप से उठाया है।

1. आरोप–पत्र का यह कथन गलत है कि दिनांक 20/7/96 के जमा की प्रति आवेदन–पत्र भुगतान के लिए दिनांक 17/8/98 को दी गई। तथ्य यह है कि आवेदन–पत्र दिनांक 21/7/96 को ही नायब पोस्ट मास्टर, बडगांव के माध्यम से प्राप्त किया जा चुका था। यह प्रतीत होता हे कि मूल आवेदन–पत्र तथा इसके क्रम में भेजे गये स्मृति–पत्र मण्डल कार्यालय से लापता है और दिनांक 17/08/98 के पूर्व के सभी पत्र फाइल पर नहीं रखे गये हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि दावा औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण मामला बन्द कर दिया गया और तद्नुसार उसे सूचित कर दिया गया किन्तु आज तक उन्हें कोई सूचना नहीं मिली हैं।
2. उसके विरूद्व आरोप लगाया है कि उसने वरिष्ठ अधिकारी को सीधे पत्राचार करके डाकतार नियम पुस्तक खण्ड दो के नियम 614 का उलंघन किया है इस नियम में ही उच्च अधिकारी के मांग पर किये गये पत्राचार के मामले में सीधे पत्र लिखना अनुमोंदित है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने रिपोर्ट मांगते समय यह नहीं कहा कि उसके द्वारा दिया गया आवेदन–पत्र उनके मांग पर नहीं दिया गया था।
3. उसने नियम 3(i) (ii) (iii) के0सी0से0 (आचारण)नियमावली 1964 प्राविधानों का उलंघन नहीं किया है।
4. निर्णय पूवाग्रह वश दिया गया है।
5. दंण्डादेश अनुचित और औचित्यहीन है तथा निरस्त योग्य है। साथही जो आवेदन–पत्र डाक नियम पुस्तक नियम 22बी/2/के प्राविधान के अन्तर्गत प्रस्तुत है उस पर डाकतार नियम पुस्तक खण्ड 2 के नियम 614 के उलंघन का आरोप लगाया जाना सर्वथा अनुचित है, अतः आरोप–पत्र न तो पोषणीय है ना तो समर्थनीय है। वह निर्दोष हैं।

5. मैने अपीलकर्ता की अपील, आरोपपत्र, दण्डादेश आदि का सम्यक अध्ययन किया।

1. अपीलकर्ता का यह कथन कि उसने दिनांक 17/8/98 के पहले सम्बधित प्रकरण पर कोई पत्र दिया था मान्य नहीं है वास्तविकता यह है कि उसने आवेदन पत्र दिनांक 17/8/98 को ही दिया था। उसका यह भी कथन गलत है कि उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी।
2. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा कोई आवेदन मांगा नहीं गया था बल्कि अपीलकर्ता ने स्वयं दिया।
3. अपीलकर्ता द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन किया गया है।
4. मांगे गये बचाव प्रत्यावेदन के संदर्भ में यह पत्र अनुशासनिक अधिकारी को प्राप्त हुआ जिसे बचाव प्रतिवेदन माना गया। दंण्डादेश पूर्वाग्रहवश नहीं दिया गया हैं।
5. आरोप–पत्र में विरचित आरोपों को लिए अपीलकर्ता जिम्मेदार पाया गया जिसके लिए उसके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाई के प्ररिणाम स्वरूप दण्ड दिया गया। दण्डादेश उचित और नियमानुकूल है।

7. अनुशासनिक अधिकारी के दण्डादेश में हस्ताक्षेप का कोई औचित्य नहीं है अपील एतद् द्वारा अस्वीकृत की जाती है।"

9. Aecording to respondents, the applicant preferred a petition dated 22.7.2002 to the Chief Post Master General. The Reversionary

Authority has considered the main points raised in the petition submitted by the applicant. The relevant extract of the order dated 8.6.2005 is reproduced below:-

"The petitioner has raised the following main points in his petition for consideration:-

3.1 that Rule 614 of P&T Manual Vol.II does not restrain the provisions of Rule 122-B(2) and 184 of Postal Man. Vol.III. The petitioner did not violate the provisions of Rule 614 on P&T Man. Vol.II.m

3.2. That the allegation is that the refund was not applied before 17.8.98 but the petitioner had sent and application for refund on 21.7.96 through SPM. The application dated 17.6.96 was in continuation ofj previous application dated 21.7.96. No proper inquiries were made and related records were not preserved.

3.3. that it is incorrect that information about rejection of claim of the petitioner was given to the petitioner.

3.4 That the petitioner visited office of Chief PMG on 9.1.2001 in connection with official duty. He met the Chief PMG and on demand he gave two separate applications one for refund of Rs. 1000/- and other for grievance in connection with departmental quarter allotted to him. The SPOs concealed the fact of second application given to Chief PMG on 9.1.2001 about departmental quarters grievances.

3.5. That the erroneous credit of Rs. 1000/- on 20.7.96 was the money of the petitioner which was handed over to him by a near relative and his claim was justified.

3.6. That the application dated 29.10.2001 of the petitioner addressed to SPOs Gonda was treated as defence representation of the petitioner but this application was for showing the document which was not shown (i.e. his second application to Chief PMG regarding grievances of departmental quarter).

4. The petition was considered carefully along with the relevant records of the case. The following facts have emerged:-

4.1 Rule -122 (B) 2 and Rule-184 of Postal Man. Vol.III are not applicable in this case. The petitioner violated the provisions of Rule 614 of P&T Man. Vol.II.

4.2. The petitioner claimed refund after two years. In inquiry, it was proved that the amount credited in UCR was not the personal money of the petitioner. The claim was therefore not justified.

4.3 The petitioner was informed about the rejection of his claim of refund vide SPOs Gonda letter dated 11.5.99 dispatched under RL 1423 dated 12.5.89.

4.4. Only one application was received through PMG Gorakhpur letter No. RPG/SB/M-15/CC/10 dated 2.5.2001. It is a fabricated story by the petitioner that he was deputed to Circle Office on 9.1.2001 by the SPOs Gonda Division. However, it is a fact that two applications were given by the petitioner at Circle Office on 9.1.2001 as per photo copy of the receipt granted by C.O produced by the petitioner.

4.5. It was not proved that the amount of Rs. 1000/- was personal money of the petitioner or the money given by the relative of the petitioner. In his application dated 3.5..99, the petitioner had said that while making changes, he had kept Rs. 1000/- along with his counter cash.

4.6. The second application as alleged by the petitioner was not received in D.O. Gonda and the case of the petitioner was decided on merits.

5. Keeping into the consideration the above facts of the case, I find no reason to interfere in the case on behalf of the petitioner. The petitioner is therefore rejected.

6. In exercise of powers conferred upon me under Rule 29 of CCS (CCA) Rules 1965, I hereby order accordingly."

10. We have heard the counsel for the parties and perused the material on record to assess the rival contentions.

11. During the final hearing, the learned counsel for the applicant raised the issue regarding competency of the Disciplinary Authority to initiate the disciplinary proceedings against the applicant on the ground that the applicant was officiating on the post of Deputy Post Master Gonda. The repondents while denying this contention state that applicant was appointed as Postal Assistant in Lucknow Division. Rest of the contention of the applicant raised in para 4.1 of the O.A. has been denied by the respondents. It was further submitted by the learned counsel for the respondents that the applicant was given only the benefit of higher grade in time bound one promotion (TBOP) and BCR on completion of 16 years and 26 years service respectively. At present , the applicant is BCR PA only. He has never been promoted to the post of HSG as Deputy Post Master Gonda in the pay scale of Rs. 6500-10500. Due to the shortage of staff and in the absence of approved regular candidate, he was however, looking after temporarily in the office arrangement only. Therefore, under provisions of Rule -13

of CCS (CCA) 1965, the Superintendent Post Offices, is fully empowered to proceed against the officer under Rule 13 of CCS (CCA) Rules and relevant schedule thereunder.

12. The second point raised by the learned counsel for the applicant is regarding denial inspection of documents /letters which were directly written by him and given to CPMG. The learned counsel for the respondents submitted that it is not correct to say that the applicant did not know about the representations dated 15.10.2001 and 29.10.2001 as he himself has mentioned these dates in his submission in para 4•3 of the O.A. When a query was raised by this Tribunal, as to what prejudice had been caused to the applicant, the counsel for the applicant could not make any submissions regarding the prejudice if any caused to the applicant in this regard. The orders dated 25.4.2001 passed by the coordinate bench of this Tribunal in O.A. No. 642/93 (Raj Kishore Shukla Vs. Union of India) which has been relied upon is not helpful to the applicant. The cited ruling is about a case of compulsory retirement where, the disciplinary proceedings were initiated for imposition of major penalty . In this O.A. it is only for imposition of minor penalty. Hence this O.A. is distinguishable on facts as well as procedures prescribed under CCS (CCA) Rules 1965 for such disciplinary p;roceedings.

13. We find from the discussions above that the disciplinary proceedings have been conducted in accordance with relevant provisions of CCS (CCA) Rules 1965 by giving fair treatment to the applicant at all stages i.e. by the inquiry officer, by Disciplinary Authority, by the Appellate Authority and by the Revisionary Authority. These authorities have given their findings based on cogent material and after proper appraisal of relevant evidence on record. Procedural provisons are generally meant for affording reasonable and adequate opportunity to the delinquent employee. They are generally speaking conceived in his interest. Violation of any or every procedural

provision cannot automatically vitiate the inqury held or order passed. If no prejudice is established to have resulted there from, no interefernce is called for as laid down by the Apex Court in State Bank of Patiala and Ors. Vs. S. K. Sharma 1996,(2) SLR-631 (SC).

14. In Union of India and Others Vs. Upendra Singh, 1994 (3) SCC 357, the Apex Court has laid down that jurisdiction of CAT is akin to jurisdiction of the High Court under Article 226 of Constitutioin. The scope of judicial review is not against the decision, but decision making process as has been clearly laid down by Hon'ble Supreme Court in case of Bank of India Vs. T. Jagram, AIR 2007 SC 2793.If no procedural irregularity/illegality in proceedings is found, principle of natural justice is not violated and no interference with the findings of authorities is warranted by the Tribunal. Considering the circumstances mentioned above, the present case is one where no intereference of the Tribunal is called for.

15. We have not found anything arbitrary or perverse in the above findings recorded by the Disciplinary Authroity and by the Appellate Authority, and by the Revisionary Authority. Therefore, we do not find any scope to interefere with the findings of the competent authorities exercising their jurisdiction under the relevant provisions of CCS(CCA) Rules, 1965.

16. In view of the facts and circumstances stated above, the O.A. is devoid of merit and is liable to be dismissed.

17. The O.A. is accordingly dismissed. No order as to costs.

22.10.12

(S.P. Singh)
Member (A)

22.10.12

(Justice Alok Kumar Singh)
Member (J)

Vidya